



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 914 राँची, गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

8 नवम्बर, 2019

कृपया पढ़ें:-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-2683(अनु०), दिनांक 29.05.2006
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या-4084 दिनांक 04.08.2006

संख्या-1/आ०-5040/2003 का.-8961-- श्री बैद्यनाथ प्रसाद, भा.प्र.से. (झा:1988), तत्कालीन उत्पाद आयुक्त, झारखण्ड, राँची, सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 31.05.2005) के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या-2683 दिनांक 29.05.2006 के द्वारा उत्पाद आयुक्त, झारखण्ड, राँची के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्नलिखित अनियमितता के लिए आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गयी:-

1. श्री बैद्यनाथ प्रसाद, भा.प्र.से. (झा:1988), तत्कालीन उत्पाद आयुक्त, झारखण्ड, राँची, सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 31.05.2005) के द्वारा रु० 1,02,956/-(एक लाख दो हजार नौ सौ छप्पन रुपये मात्र) की सरकारी सम्पत्ति गायब किया गया।

उपर्युक्त वर्णित कार्यकलाप अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1969 के प्रावधान के तहत “मिसकंडक्ट” पाया गया।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या- 4084 दिनांक 04.08.2006 के द्वारा श्री बैद्यनाथ प्रसाद, भा.प्र.से. (झा:88) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री एन०एन०पाण्डेय, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में श्री कौलेश्वर प्रसाद, अवर सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को नियुक्त किया गया।

श्री एन०एन०पाण्डेय, भा.प्र.से. द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री प्रसाद के विरुद्ध मात्र रु0 23,634/-मूल्य के सॉफ्टवेयर/ सी०डी० को विभाग में वापस न लौटाने के आरोप को लगभग प्रमाणित माना गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री बैद्यनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात इनके पेंशन एवं ग्रेच्युटि की राशि से रु० 23,634/-वसूलने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने हेतु भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अनुरोध किया गया था।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मामले की समीक्षा करते हुए निष्कर्ष के रूप में निम्न परामर्श दिया गया-

"The Commission conclude that from the foregoing analysis based on evidences and statements, the Article of Charge framed against the MoS is not 'conclusively proved'.

In the light of the observations and findings as discussed above, and after taking into account all the aspects relevant to the case, the Commission consider that the proceedings initiated against the MoS, Shri Baidya Nath Prasad be dropped and he be exonerated from the charge levelled against him."

संघ लोक सेवा आयोग के उक्त परामर्श पर भारत सरकार द्वारा निम्नवत आदेश पारित किया गया:-

"NOW THEREFORE, in view of the aforementioned facts and after considering all relevant records, the Disciplinary Authority in Central Government has agreed with the advice of the UPSC and the proposal of the State Government of Jharkhand and accordingly decided to drop the Disciplinary Proceedings against Shri Baidyanath Prasad, IAS (JH:1988) (Retd.) and exonerate him."

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत अंतिम आदेश के आलोक में श्री बैद्यनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (झा:1988) के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक मामले को समाप्त करते हुए इन्हें दोषमुक्त करने तथा श्री प्रसाद को रोके गये उपादान एवं पूर्ण पेंशन भुगतान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
